[श्री विभूति मिश्र]

प्रोफैसर रहे हैं। यह बात भी है कि सौ में से अस्सी आई० ए० एस० के अफसर दिन में सोते हैं। किसी आफिस में जा कर आप देख लो। महाभारत में पूछा कि साहब, आदमी क्यों मर गया तो जवाब मिला कि इस लिये मर गया कि दिन में सोया था। हमारे सरकारी नौकर भी दिन में सोते हैं तब उन से क्या फायदा होने वाला है ?

एक माननीय सदस्य : रात में काम करें तब क्या हो ?

श्री विभूति मिश्र : रात को काम करें तब दिन में सोयें। मैं कहना चाहता हूं कि प्रमोशन तब होना चाहिये जब कोई अच्छा काम करे। जो होशियार आदमी हो उसे प्रमोशन मिलना चाहिये। सर्विस में जो भी अच्छा काम करे, पूरा काम करे उस का प्रमोशन जरूर होगा यह भी होना चाहिये।

एक और बहुत बड़ी बात यह है कि यू० पी० एस० सी० ने जो अंग्रेजी को कायम रक्खा है उस को हटा देना चाहिये। जो रीजनल भाषा हो उस को रखना चाहिये। मैं दावे से पूछना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी जानने वाले हैं उन्होंने पिछले अठारह वर्षों में क्या किया ? मैं चेलेन्ज कर के पूछता हूं कि किस फ्रंट पर कुछ काम किया गया है ? फूड फ्रंट पर, एजूकेशन के फ्रंट पर, एग्रीकल्चर के फ्रंट पर सोशलिज्म के फ्रंट पर उन्होंने क्या किया ; अभी हमारे यहां अंग्रेजी का ही राज्य चलता है क्योंकि अंग्रेजी जानने वाला क्लास यह सोचता है कि हम अंग्रेजी जानते हैं इस लिये हमारा काम होना चाहिये। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० एस० सी० के इम्तहान वगैरह जो हैं वह रीजनल लैंग्वेज के मीडियम से होने चाहियें। और इसी तरह से लोगों को बहाली मिलनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब आप अपनी तकरीर आज बन्द कर दीजिये। आप 28 मिनट ले चुके हैं। आप का जो प्वाइंट आफ आर्डर है उस को भी दूसरे दिन लेंगे।

Shri S. M. Banerjee: May I raise a point of order? First, let me state the relevant rule.

Mr. Chairman: His speech is not finished yet. On the next day when this item is taken up, this point of order also will be taken up.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मेरा एक अमेंडमेंट भी है।

---

17 hrs.

FOOD ZONES*

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : सभापति जी, देश की खाद्य स्थिति के खराब होने का मुख्य कारण जहां हमारे देश में खाद्यान्नों का अभाव है वहां उस का एक मुख्य कारण दोष पूर्ण वितरण प्रणाली और खाद्यान्नों को बनावटी दीवारें भी हैं। केरल की हालत पर अभी दस दिन पहले काम रोको प्रस्ताव उपस्थित करते हुए मैं ने खाद्य मंत्री से कहा था और चेतावनी दी थी कि यदि इस स्थिति को जल्दी नहीं सम्भाला गया तो जो घटनायें केरल में हो रही हैं वह दूसरे प्रान्तों में भी फैल सकती हैं। अभी दो दिन पहले बंगाल विधान सभा और विधान परिषद् में जो दृश्य उपस्थित हुए हैं उन से हमारे खाद्य मंत्री अच्छी तरह परिचित होंगे। इस के साथ अगर अभी भी यह स्थिति नहीं संभाली गई तो मैं दुबारा चेतावनी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो यह आग केरल या बंगाल में फैली है वह अगर दूसरे प्रान्तों में फैल गई तो यह पार्लियामेन्ट हाउस भी उसकी लपट से बच नहीं सकेगा। देश की स्थिति इतनी खराब होने जा रही है

*Half-An-Hour Discussion.

खाद्यान्नों के क्षेत्रों को समाप्त किया जाये इस सम्बन्ध में कभी कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में देखा था कि जयपुर कांग्रेस में बहुत बड़े बहुमत से इस विषय पर बल दिया गया था कि खाद्यान्नों के जोनों को समाप्त किया जाये । समाचार पत्रों में यह भी था कि संसदीय कांग्रेस पार्टी की निजी बैठक हुई थी । उस में भी इस बात पर बल दिया गया था कि खाद्यान्नों के क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाये। इसी प्रकार से देश के जितने भी दूसरे राजनीतिक दल हैं, जन संघ है, स्वतन्त्र पार्टी है, पी० एस० पी० है, और अगर मैं भूल नहीं करता तो हमारे देश की कम्युनिस्ट पार्टी भी इस पक्ष में है कि खाद्यान्नों के जो क्षेत्र हैं वह समाप्त होने चाहियें क्योंकि उनसे देश में बहुत विषम स्थिति पैदा हो रही है । मैं समझ नहीं पाता कि जनतन्त्र की दुहाई देने वाली इस सरकार में कौन ऐसा तानाशाह बैठा हुआ है जो इतने प्रबल जनमत के होने पर भी फूड जोन्स को कायम रखे हुए है ।

खाद्यान्नों के क्षेत्र को बनाये रखने का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एक ही देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं । उदाहरण के तौर पर मैं बतलाता हूं । पंजाब के अन्दर गेहूं का भाव 56 रु० प्रति क्विंटल है, लेकिन वही गेहूं उत्तर प्रदेश में आकर 85 से 90 रु० प्रति क्विंटल तक बिकता है और महाराष्ट्र में उसी गेहूं का भाव है 150 रु० प्रति क्विन्टल । चने का भाव पंजाब में 55 रु० से लेकर 58 रु० तक है जब कि दक्षिण भारत में उसी चने का भाव 125 से 150 रु० क्विन्टल तक है । चावल के सम्बन्ध में मैं बतलाता हूं कि जो चावल आंध्र में 80 रु० क्विन्टल है मद्रास में वही चावल 85 रु०, मैसूर में 120 रु० और केरल में 200 रु० प्रति क्विन्टल तक बिकता है । जब दूसरे देशों में भारत की खाद्यान्न की स्थिति बिगड़ने के कारण भीख मांगने की स्थिति पैदा हो गई है और दूसरे देशों के छोटे छोटे बच्चे हमारे देश में खाद्यान्न भेजने के लिये धन इकट्ठा कर रहे हैं, उस समय इन फूड जोन्स के बने रहने से खाद्यान्नों की कितनी हानि हो रही है जरा इसको भी तो देखिये । आज भिन्न भिन्न मंडियां और भिन्न भिन्न नगरों में हमारे देश का करोड़ों मन गल्ला सड़ रहा है । उदाहरण के लिये पंजाब के जो मोटे मोटे आंकड़े मुझे उपलब्ध हो सके उन को बतलाता हूं । पंजाब में इस समय लगभग 15 लाख मन गेहूं रुका हुआ है, 40 लाख मन चना रुका हुआ है और उसी पंजाब में मक्का और बाजरा लगभग 25 लाख मने रुका पड़ा हुआ है । आज पंजाब में खाद्यान्न का जो भाव है उसी हिसाब से सारे खाद्यान्नों का मूल्य ले लिया जाये तो करीब 16 करोड़ रु० से ऊपर का खाद्यान्न पंजाब में बेकार पड़ा हुआ है ।

यह हालत वहां पर तब है जब नई फसल आने की तैयारी कर रही है । पुरानी फसल का जितना भी खाद्यान्न है वह पंजाब की मंडियों में और किसानों के घर से बाहर नहीं आ सका है । यह आंकड़े तो केन्द्रीय सरकार की अपनी रिपोर्ट में हैं कि पंजाब के लुधियाना जिले में पिछले साल 50 प्रतिशत से भी अधिक फसल गेहूं की हुई है । लुधियाने की जो सब से बड़ी मंडी मोगा की है वहां से कुछ लोग आये थे उन्होंने अपने गेहूं का नमूना दिया है । अगर आप उचित समझें तो मैं उसे टेबल पर रख दूंगा और अगर नहीं तो खाद्य मंत्री जी को दे दूंगा जिस से पता लग जायेगा कि आज किस प्रकार लाखों मन गल्ला वहां सड़ रहा है । जब हमारे देश में खाद्यान्न के अभाव के नाम पर दूसरे देशों के छोटे छोटे बच्चे झोली फैला कर भारत के लिये भीख मांग रहे हैं । पंजाब के लोगों का विचार है कि नई फसल आने को है और पुरानी फसल का गल्ला निकल नहीं पाया है । वह तो यहां तक कह रहे हैं कि जो गेहूं सरकार बाहर से मंगवाती है उसका किराया लगाने के बाद जिस भाव पर भारत में वह गेहूं पड़ता है उसी भाव पर उन का गल्ला

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

खरीद लिया जाय । अगर इतना ही कर दिया जाये तो कम से कम व्यापारियों और किसानों को सन्तोष हो जायेगा ।

अब पंजाब के साथ साथ में दूसरे प्रान्तों की स्थिति भी आप को बतलाता हूं । राजस्थान में अजमेर और दूसरे व्यापारिक नगरों की क्या स्थिति है ? उसके बारे में मेरे पास एक पत्र आया है जिस को मैं खाद्य मंत्री जी को देना चाहता हूं । उस पत्र में लिखा हुआ है कि राजस्थान में 30 लाख बोरी चना इस समय रुका पड़ा है । अगर एक बोरी को ढाई मन तक भी मान लिया जाये तो 75 लाख मन चना राजस्थान में रुका हुआ है । राजस्थान में चने का भाव 45 से 50 रु० तक है । लेकिन जब वही चना साथ में लगते हुए गुजरात में बिकता है तो 110 से 120 रु० तक बिकता है । अब आप ही अनुमान लगाइये कि खाद्यान्न के जोन देश में कितनी विषम स्थिति पैदा कर रहे हैं ।

इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 लाख मन चना रुका पड़ा है । इस का दुष्परिणाम इस समय यह हो रहा है कि उन राज्यों की सरकारें व्यापार करना शुरू कर देती हैं । बाद में फिर दूसरी सरकारें भी ऐसा ही करना शुरू कर देंगी । पंजाब की सरकार ने 39 रु० क्विन्टल मक्का खरीदा लेकिन उस को उस ने मुनाफे पर बेचा । नागपुर में उस ने उसी मक्का को 80 रु० क्विन्टल बेचा । अर्थात् सेंट पर सेंट मुनाफा कमाया महाराष्ट्र से । पंजाब सरकार ने 56 रु० क्विन्टल पर चना खरीदा लेकिन पजाब सरकार वह चना बंगाल गवर्नमेंट को 90 रु० पर बेच रही है । अगर व्यापारी मुनाफा कमाये तो वह फौरन डी०आई०आर० में आ जाता है, लेकिन अगर सरकार मुनाफा कमाती है दूसरी सरकार से तो केन्द्रीय सरकार के कानों पर किसी प्रकार जूं नहीं रेंगती है ।

Shri Ranga (Chittoor): If the merchant does it, it is profiteering, but if Government does it, it is sacred duty! This is sheer profiteering, Sir.

सभापति महोदय : एक चीज है । यह एफ० ओ० आर० पंजाब है या एफ० ओ० आर० बंगाल है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पंजाब की गवर्नमेंट से आज बंगाल की गवर्नमेंट पंजाब में खरीद रही है उस में ही इतने मुनाफे का भाव है यह मैं कह रहा हूं । जो इस प्रकार से मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि राज्य सरकारों के अन्दर एक संकुचित मनोवृत्ति पैदा हो रही है । एक जगह चावल का स्टाक जमा है और दूसरी जगह बंगल के राज्य के लोग भूख से मर रहे हैं । इसी का दुष्परिणाम यह हुआ कि मध्य प्रदेश की सरकार में भोपाल से छत्तीसगढ़ में, जो कि उसी राज्य का एक भाग है अन्न नहीं पहुंच पाया । जब छत्तीसगढ़ में आन्दोलन हुआ तब मध्य प्रदेश की सरकार ने विवश हो कर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में उसके भेजने की बात स्वीकार की ।

मैं जिस प्रान्त से आता हूं, अर्थात् उत्तर प्रदेश, उस प्रांत की बात मैं आप को बतलाता हूं । वहां पर एक जिले से दूसरे जिले की सीमा जहां मिलती है वहां पर बैरियर्स बने हुए हैं । वहां से अन्न दूसरे स्थान में नहीं जा सकता । मुरादाबाद का गेहूं मेरठ नहीं जा सकता और मेरठ का गेहूं बुलन्दशहर नही जा सकता । यह वह देश है जो समाजवाद में विश्वास करता है । लेकिन भले ही सारा देश भूखों मर जाये पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न नहीं जा सकता है । सारे देश में आज यह स्थिति पैदा हो रही है । इस का दुष्परिणाम यह हो रहा है कि पहले तो खाद्यान्नों को बड़े बड़े व्यापारी रोका करते थे लेकिन अब जो समृद्ध किसान हैं, जिन के पास बड़े बड़े फार्म हैं उन्होंने भी गल्ले

को रोकना शुरु कर दिया है और आज गल्ला उन के पास भी रुका पड़ा है। तीसरा इसका दुष्परिणाम यह है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार, ब्लैक-मार्केटिंग और पुलिस जो सीमा पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गल्ला पास कर देती है इस प्रकार की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती चली जा रही है कि गल्ला चला जाता है दूसरी ओर। पंजाब से उत्तर प्रदेश में, गुड़गांव से कोसी की मंडी में गल्ला जाता है। सड़क से अगर गल्ला पास हो तो पुलिस ट्रक वालों को पहचानती है कि इस प्रकार के ट्रक वाले इस तरह का माल ले जाते हैं। पुलिस के साथ उनकी सांठ गांठ रहती है। लेकिन जो बेचारे उनको कुछ पैसा नहीं दे पाते वह पकड़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से गाजियाबाद की ओर गेहूं ले जाते हुए यहां के चीफ कमिश्नर ने पकड़ा था। लोग सरों पर गठरी रखकर शाहदरा के रास्ते ले जाते हैं। ऊंटों पर और दूसरे प्रकार से इस तरह का गल्ला भेजा जाता है।

एक यह पत्र मेरे पास आया है पंजाब के किसी एक बड़े फार्म के मालिक ने भेजा है। हीरा फार्म है शायद, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। यह भी मैं आपको देना चाहूंगा इससे भी आप पता लगायें। यह लिखता है कि अगर यह कोशिश सरकार की रही कि हम गेहूं और चना अच्छी अच्छी चीजें उत्पादन करें और हमें अपने उत्पादन का अच्छा पैसा न मिले तो कल को अगर हम मूंगफली और कपास जैसी कैश क्राप पैदा करने लगें उधर हम अपनी प्रवृत्ति को मोड़ दें तो सरकार हमको उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकती। फिर तो खाद्यान्नों की स्थिति कल को और भी बिगड़ती चली जायगी।

एक बात सबसे अन्त में कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभापति जी, यह कहा जाता है कि खाद्यान्नों के जोन समाप्त हो जाने से जो अन्न का भाव महंगा हो जायगा उसको रोकने का क्या उपाय है। देश के कई नेताओं और कांग्रेस प्रेसीडेंट तथा शायद है कि खाद्य मंत्री के मस्तिष्क में भी यह बात है। मैं दिल्ली शहर का उदाहरण देता हूं। दिल्ली से बाहर का नहीं। जब तक दिल्ली में खाद्यान्नों के जोन नहीं बने उस समय नवम्बर सन् 62 में गेहूं 38 रुपये से 41 रुपये क्विंटल तक और नवम्बर 1963 में 47 रुपये से 49 रुपये क्विंटल तक था। लेकिन जब जोन बन गया तो 64 में गेहूं का भाव 95 से लेकर 100 रुपये क्विंटल तक और 65 में 74 से 76 रुपये क्विंटल तक हो गया। हो सकता है यह जोन जब आप समाप्त करेंगे तो एक बार भाव फिर ऊपर को जायं? जैसे गुड़ से आपने कंट्रोल समाप्त किया था कंट्रोल समाप्त करते ही उत्पादक को कुछ पैसे ज्यादा मिलेंगे फिर जब गुड़ का आना जाना शुरू हो गया तो कीमत हर प्रान्त में निश्चित रूप से एक स्थान पर आ गई। इसी प्रकार जब सीमेंट से कंट्रोल हटा तो उसका परिणाम यह है कि आज सीमेंट लोगों को मिलने लगा। जो पहले ब्लैक के अन्दर 21 और 22 रुपये बोरी मिलती थी आज वह बुराई से भी अगर मिलती है तो 11 और 12 रुपये तक ज्यादा से ज्यादा मिलती है। लेकिन देशको मिलती तो है, लोग अपना काम तो चलाते हैं। तो मेरा अपना कहना यह है कि अगर यह खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त कर दिये जाय तो लाखों और करोड़ों मन गल्ला जो देश की मंडियों बेकार पड़ा हुआ है वह सड़ेगा नहीं। उत्पादक को ठीक पैसा मिलेगा और देश के अन्दर जो खाद्यान्नों के अभाव की कृत्रिम स्थिति पैदा हो गई है यह कृत्रिम अभाव की स्थिति नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि सरकार बार बार चेतावनियां सुनने की आदत न डाले और अपनी खाल को खाद्य मंत्री जी मोटी न बनायें। जनतंत्र के अन्दर विश्वास करने वाले खाद्य मंत्री जनतंत्र की आवाज को एकदम सुनें और यह घोषणा करें कि देश में खाद्यान्नों के क्षेत्र समाप्त किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय : (श्री सिंहासन सिंह से) आपका नाम नहीं है इसमें।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : मैंने भेजा है। मैंने हिन्दी में लिखा है, शायद आप पढ़ न पाये हों।

सभापति महोदय : हिन्दी थोड़ी बहुत मैं पढ़ सकता हूं।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : मैंने अपना नाम भेजा है।

सभापति महोदय, जो प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं गया है। मैं वर्तमान खाद्य मंत्री को 33 वर्षों से जानता हूं और उनके जेल जीवन से जानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि डेमोक्रेसी की ओपिनियम हो, जो जनता की आवाज हो, उसको वह न सुन सकें। जो खाद्य स्थिति हमारे देश की है....

सभापति महोदय : स्पीच आप नहीं दे सकते। वक्त कम है। सवाल आप कर सकते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : सवाल मुझे नहीं करना है।

Shri Ranga: I think the hon'ble Minister is aware of the onset of what is known as the belt area.

If he does not know I would like him to make enquiries about it. These belt areas are small Keralas, between district and district as my hon. friend has put it, between state and state. My own constituency is suffering because it is the border of Mysore and Madras. In these border areas stretching over ten miles between these two States people who live there continue to suffer, suffer more than the Kerala people. Besides, the headloaders as they are called, carry 50-60 lbs. on their heads from the nearest markets to the local people and supply it to them and some others also carry these loads as payments received for their agricultural labour in the outside areas and carry it to their own homes. These people are now being troubled by the local police and local revenue authorities.

17.15 hrs.

[SHRI P. K. DEO *in the Chair.*]

Would the government see that this system is abolished and the head-loaders are not unnecessarily troubled in this way. If they just wish to prevent smuggling from one area to another, they may have their own police organisation just on the border without unnecessarily troubling these people in these so-called belt areas of ten miles. It affects the people not only of the villages but also of towns, important places like Adoni, Palamener, Ponganur' Madagasira and so many other places on the border.

Would the government put an end to these belt areas? Also would the government not close their mind to the demand for the abolition of the zonal restriction but keep an open mind and begin to withdraw these restrictions in progressive stages, first of all removing them between district and district and also abolish these belt areas and increasing the quantum of foodgrains that may be carried by agricultural workers and other people also on their heads from place to place and would they introduce, in the place of a kind of monopoly that they now have, a kind of a competitive system and allow their co-operative stores and the private traders and through their foodgrains corporation also, introduce an element of competition so that the consumers could be protected. I am giving these suggestions pending the decision of the government which we expect would be taken very soon for the abolition of the zonal system.

Shri Sinhasan Singh: Which of the different States are surplus, which self-sufficient and which deficit; and if so, in what ratio to their own population they are surplus, sufficient or deficient?

Shri B. K. Das (Contai): In the agricultural prices commission's dissenting note these matters were pointed out that there would be these difficulties about the working out of a single zone system. I want to know whether after the experience of several months, about a year or so now, what was pointed out in the dissenting note has come to be true or the experience has proved otherwise? What is the experience of the working of this system?..(*Interruptions.*)

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : जो प्रकाशवीर शास्त्री जी ने बात कही, वह हर प्रान्त में बात है। मेरी रिक्वेस्ट यह है है मिनिस्टर साहब से कि जैसे महाराष्ट्र में कम्पल्सरी प्रोक्योरमेंट, डस्ट्रीब्यूशन और जो जो काम करते हैं और जो किसी और को करने नहीं देते जिससे लोगों के पास मंडी में गल्ला ले जाने का कोई कारण नहीं, सब गल्ला सरकार के पास आता है और महाराष्ट्र सरकार ने जो रूल बनाया है कि 5 एकड़ तक कोई लेवी कम्पल्सरी नहीं है इसे 10 एकड़ तब सरप्लस में से 60% और 10 से 15 एकड़ तक 65 परसेंट जो सरप्लस है उसमें से लेंगे और हर आदमी के लिए डेढ़ क्विंटल गल्ला रखने का इन्तजाम किया है ऐसा 50 एकड़ तक कियातो इस रीति से सब प्रान्तों में व्यवस्था हो जाय जिससे कि गल्ला किसी जगह पर खराब न हो और यहां इधर उधर भाव ज्यादा न हो, ऐसा इन्तजाम सेंट्रल गवर्नमेंट हर प्रान्त को कह कर या आर्डर देकर क्यों नहीं करती ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri C. Subramaniam): Mr. Chairman, Sir, I am quite aware of the feelings, not only of some of the hon. Members but also the feelings outside that the zonal system should be examined thoroughly and, if necessary, some changes should be made. The point for consideration is this: first of all, is there a food problem or not, and whether we have sufficient foodgrains to feed our people, or we are functioning in a deficit economy. Some people—I do not know for what purpose—have been emphasising that there is absolutely no food problem and that it is because of the zones and the defects in the distribution system that all the difficulties are arising. With great respect to them, I would like to submit that, if we take the production figures during the last five years, except for a spurt last year, we have been producing at a lower level than the last of the third Five Year Plan. On the other hand, the population has been increasing at the rate of almost 12 millions every year. Therefore, during these five years, there has been an increase in population by about six crores, against which the increase in production is almost nil. We have been working, for some time, if any, below the level of the last year of the third Five Year Plan. Therefore, to suggest, as some hon. Members have suggested, that production has increased along with the population—I respectfully submit—is not correct. It may be that we may not be able to evaluate our production even to a million tons, but broadly, the trends are known. Therefore, I beg to submit that we are functioning in a deficit economy as far as food is concerned.

In this deficit economy, how to manage the situation is a matter for consideration by the Government and indeed for the country as a whole. It is not as if we have a perfect system or the best system against which we have chosen one of the worst systems. It is not so. In trying to find out how to manage this deficit economy, we have four to five alternatives. The first alternative which could be considered would be free trade throughout the country; free movement, and the market condition to adjust according to the demand and supply, and whoever has got the purchasing capacity will be able to purchase and whoever does not have it, he will have to fall under. We could leave it to the free trade to function in the best way possible and say, "we are not concerned with it; it is market operation—*laissez faire*, and

[Shri C. Subramaniam]

therefore demand and supply laws will function and therefore we can leave it at that." Or, we can go to the other extreme, saying that we shall procure every procurable surplus from every producer, and than taking into account what we are able to procure, we shall have and equitable distribution on system throughout the country making an average and then distributing according to manual labour, child or an ordinary adult.

Now, either of these things is not possible in the present circumstances. Shri Prakash Vir Shastri argued that if it is left to free trade, the producers also are likely to get a fair price. We have experience of free trade. Our exprience is, unfortunately, the producer is compelled to part with his produce soon after the harvest, because he has got so many demands and pressures. It is the trader who is able to get it in a free trade, and on that basis, the producer not only suffers immediately after the harvest, one is able to get the highest price only when there is scarcity, the lean period. Sometimes, it is not merely the natural loan periods, but for the purpose of higher profits, even artificial scarcity and lean periods are created by the traders. The philosophy of trade is to make as much profit as possible and the best trader is he who makes the highest profit. You cannot blame him. So, we came to the conclusion that we cannot allow free trade to function.

Is it possible to have monopoly procurement from every producer? In a deficit economy, that would mean trying to find out what is the surplus with every producer. Who is to estimate the surplus? Not the Secretary or the Minister. Ultimately the lowest officer with the assistance of perhaps the village official has to findout how much a person has grown, what is the area, what is the estimate of produce, what is the estimate of his requirements and what is the surplus.

Shri Vasudevan Nair: That is no excuse.

Shri C. Subramaniam: I have functioned in a system of monopoly procurement in Madras and I know what difficulties it leads to. All the big fish escape and ultimately it is the smaller and middle producer who suffers. All sorts of difficulties arise. So, we have to find a *via media* between the two. Any sort of control is irksome, I agree. In the present context, we have to find out which is the best amongst the alternatives available.

Another way of doing it would be to have a national levy on every big producer having 2 or 3 or 5 acres, according to the productivity of the area and the consumption pattern. Then, if we procure on that basis, we will be able to control the market with some quantities of grains available with us. On that basis, we can get certain quantities into the hands of the Government and have controlled distribution, particularly in the urban areas by cordoning them off and leave the rest of the country as a free zone with market conditions functioning as best as possible. We can have some fair-price shops in the semi-urban areas and also in rural areas wherever there is scarcity. That is another way.

Yet, there is a refinement in this levy. Instead of spreading it out throughout the country and trying to find out who is the big producer in every village, we can concentrate in the surplus districts. There are 52 surplus districts in foodgrains. We can concentrate on them, try to get certain quantities, have controlled distribution, cordoning off cities, have fair-price shops and informal rationing. For all these purposes, we can find out what would be the requirement and we can operate that also.

Another alternative is, instead of leaving the whole country free and allowing scarcity pockets to develop without any plan and allowing move-

ments from one area to another freely, we can have zones, not necessary State zones, but bigger zones and allow free movement within those zones. This was also operated. But when scarcity conditions are acute, unfortunately the zones have no executive authority which can function within these zones of three or four States. For instance, we had the southern zone consisting of Madras, Andhra, Mysore and Kerala. If we have to see that there is either control of movement or control of prices, unless in all the areas it is possible to control it, having control in one area and no control in another area leads to distortion. This is what happened in the southern zone. We had a maximum price fixed. That maximum price was enforced in Andhra. That maximum price was enforced in Madras. But as far as Kerala was concerned it was interested only in getting more rice from the other areas. Therefore, they shut their eyes even though a decision was taken with regard to enforcement of the maximum price. Therefore, the flow of rice was from the surplus States to the State of Kerala and the surplus States immediately got into difficulties. When it is a zone with more States there is no executive authority to function within the zone. The executive authority is confined to each State. The result is that Madras State cannot function in Kerala nor can Andhra State function in Kerala. Therefore, there is no executive authority in these zones. Unless there is greater co-operation between all the States and they strictly enforce all the rules and decisions agreed upon, it leads to great difficulties.

It is in that context that we had to break it. The other alternative is to have States as zones, and then on that basis try to find out the production of each State, see how much is produced there, see what has been the pattern of consumption there, assess its surplus as best as possible and assess the deficit as best as possible. It is not as if when we have State zones the integrity of the country is broken.

Shri Ranga: What else?

Shri C. Subramaniam: What happens is, instead of trade moving the surplus from one State to another the surplus is moved from State to State. For example, Andhra rice is still going to Kerala, not by free trade but on the basis of Government to Government. Andhra rice is still being consumed in Kerala. Madras rice is still being consumed in Kerala. In the same way, Andhra rice is consumed in Madras, but it is done on a Government to Government basis, on a State trading basis. This is how it happens. But I do agree that in this also unless the State Governments, particularly the surplus State Governments, realise their responsibility and deliver the surplus available with them it leads to difficulties. It has led to difficulties.

What I want to impress upon the House now is, it is not as if we just chose off hand one alternative. We have experienced the various alternative systems and ultimately, having considered every alternative, the Chief Ministers and the Ministers here chose this system. I do not say it is a perfect system. But what is the alternative? People now say, abolish the State zones. But what next? You will find as many suggestions as there are individual members in this House, or at least as there are parties in this House. Shri Vasudevan Nair would say, abolish the zones but have monopoly procurement.

Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha): Yes (*Interruptions*).

Shri C. Subramaniam: Monopoly procurement would mean not only State zones, not only district zones, not only taluk zones but even village to village zones. Otherwise there cannot be monopoly procurement (*Interruptions*).

Shri Vasudevan Nair: We are not against zones.

Shri C. Subramaniam: That is not understood at all. Even if they understand it they are not prepared to accept the implications. It is not

[Shri C. Subramaniam]

abolition of zones they are pleading for they are pleading for introduction of zones village-wise. That should be understood. What is to happen after abolition of zones is a confused picture, as far as I am able to get the advice from the various parties. Sometimes it is said, have an all-party committee for solving the food problem. What happens is each party is polarised with regard to these views. How am I to evolve a national policy?

Shri Prakash Vir Shastri made the point that there are large stocks available with the merchants in Punjab. Even if it is not as much as it is represented, I do agree that significant quantities are there. What do they want? I am prepared to purchase them at a reasonable price. We cannot allow them to take the stocks to other States and sell at a higher price. Having purchased them at controlled rates from the producer the merchants want freedom to take them away and sell at an exorbitant price. If they do that we are penalising them and that is why it becomes difficult.

Shri U. M. Trivedi: (Mandsaur): Do not allow the grain to rot.

Shri C. Subramaniam: About the belt area, once the zones are there, just as we used to have belts when prohibition was introduced, it becomes inevitable. That will be there. The question is whether we should abolish the zones or not.

A question was put with regard to the recommendations of the Agricultural Prices Commission. We have accepted them. We were asked about our experience in working it. There has been difficulty in the working of that. Whether the other alternative would have worked better is a matter which has to be taken into consideration.

The Maharashtra compulsory procurement and levy was brought into the picture. That is all inevitable in a controlled economy. Therefore, we are now in the process of examining it. As pointed out even by Shri Ranga, it is not as if overnight we can change the system. It will only lead to chao. If it is not good, what is the next alternative we want to adopt is the most important thing. That will have to be examined. Even after taking a decision, the change-over cannot be made overnight; it will have to be planned and brought about gradually. That is accepted even by Shri Ranga. What is important is not the abolition of zones but what is the next alternative. An expert committee is going into it and its recommendations will be coming soon. We shall examine it and, as soon as possible, we shall consider the other alternative. I hope that other alternative will be a better one and not a bad one.

17.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 28, 1966/Phalguna 9, 1887 (Saka).

GMGIPND—L S II—2630(ai)LS—28-4-66—970.